utilisation of fund was less as limited number of suitable proposals were received.

Famine in Rajasthan

1276. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether despite good rains and floods in many parts of Rajasthan, the State is heading for a famine this year;

(b) if so, whether several districts in the State where no rainyflood situation arises are also under famine constantly;

(c) if so, whether the Central Government propose to send a Central Team to Rajasthan to investigate the districts affected by famine; and

(d) the assistance the Central Government propose to provide to the State Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) According to the Government of Rajasthan, 25468 villages in 29 districts are experiencing drought conditions in varying degrees. However, it is a fact that rainfall has been above normal in most parts of Rajasthan in the current year.

(c) There is no proposal at present to depute a Central Team.

(d) Government of Rajasthan has a Calamity Relief Fund allocation of Rs. 168.99 crores for 1995-96, out of which Rs. 126.74 crores is contributed by the Government of India.

मध्य प्रदेश को सिंचाई हेतु धनराशि का आवंटन

1277. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को सिंचाई हेतु जिलावार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में जिलावार कुल कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया हैं;

(ग)क्या सरकार ने राज्य के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की कमी और मानसून की अनियमितता जन्य प्रतिकूल प्रभावों के संदर्भ में कोई सर्वेक्षण करवाया हैं;

(घ) यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या हैं;और

(ड़) इस योजना की शेष अवधि के दौरान जिलावार कौन-कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होने की संभावना हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगैया नायडू): (क) और (ख) मंत्रालय वार्षिक आधार पर केवल राज्य स्तर पर सृजित सिंचाई क्षमता का और आबंटित की गई निधियों का परियोजना/योजना –वार ब्यौरा एकत्र करता हैं और रखता हैं । मध्य प्रदेश का अपेक्षित उपलब्ध विवरण निम्नलिखित हैं:

क्षेत्र		किया गया व्यय (करोड़ रूपए में)		सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)
	1993-94 (वास्तविक)	1994-95 (संशोधित परिव्यय)	आठवीं योजना का लक्ष्य (1992-97)	संभावित उपलब्धियां (1992-93 से 1994-95 के दौरान)
वृहद एवं मध्यम लघु कमान क्षेत्र विकास-	318.89	242.10	450.00	202.00
(i) राज्य क्षेत्र	9.61	13.00	-	-
(ii)केन्द्रीय क्षेत्र	2.89	1.63	-	-

(ग) जी,नहीं।

(घ) और (ड़) प्रश्न नहीं उठते।

Education of Scheduled CastcySchcdulcd Tribes in Punjab

1278. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state the number of SC/ST students who have completed their education upto primary level/middle level/matriculation level/ higher secondary level/Graduation level and post Graduation level during the period 1994-95 in the country particularly in the State of Punjab, State-wise and Union Territory-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): Provisional estimates of SC/ST students enrolled at various stages of education during 1994-95 are given in Anncxure. *[See* Appendix 175, Annexure No. 34.] The information regarding number of SC/ ST students who have completed each stage is not maintained by the Ministry.

हिमाचल प्रदेश में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

1279. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, सरकार और स्थानीय जनता द्वारा सरकार से वर्ष 1966 के उपरांत हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के गद्दियों और गुर्जरों को भी 1966 से पूर्व हिमाचल में बसे गद्दियों और गुर्जरों की भांति अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अनुरोध किया गया हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(ग) सरकार द्वारा पुराने अर्थात् 1966 से पहले के हिमाचल प्रदेश और नये अर्थात् 1966 के बाद के हिमाचल प्रदेश के निवासियों से संबद्व इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (**श्री सीमाराम केसरी**): (क) और (ख) जी हां। उन क्षेत्रों जो वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य को स्थानान्तरिक किए गए थे से संबंधित गद्दी तथा गुर्जर समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित करने के लिए जन प्रतिनिधियों,राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों से अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में इस प्रस्ताव की जांच की जा रही हैं।

Diminishing Expenditure on Horticulture

1280. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the reasons for the diminishing expenditure on Horticulture during the last three years when compared to a target of Rs. 1,000 crores set under the Eighth Plan;

(b) the planned development projects, under implementation both for horticulture and floriculture under the Eighth Five Year Plan; and

(c) the efforts underway to develop hybrid varieties of Mango, Guava, Banana and Cashew?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM); (a) The release of funds during the first two years of VIII Plan was relatively low as approvals for major schemes could be obtained only by the end of November, 1993. The major components of the scheme for horticulture development are for creating infrastructural facilities, which have a comparatively longer take off period. However, from 1994-95 onwards, releases and expenditure have picked up and are expected to gain further momentum in the last two years of the Eighth Plan.

(b) The development programmes in horticulture under implementation cover ongoing scheme for improving productivity & production of fruits,